

प्रेषक,

सीरम जैन,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०,  
देहरादून।

सूजा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 13 जनवरी, 2010

विषय:-

जल विद्युत निगम की नाबार्ड से वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु RIDF-XIII एवं  
RIDF-XIV के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

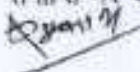
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 503/UJVNL/MD/C-28, दिनांक 28.10.2009 के अनुक्रम में  
वित्तीय वर्ष 2009-10 में नाबार्ड की RIDF-XIII एवं XIV योजना के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के  
निर्माण/सुधारीकरण/उच्चिकरण के लिये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि  
रु० 3,30,70,000.00 (रु० तीन करोड़ तीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय  
हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
(क) नाबार्ड की RIDF-XIII के अन्तर्गत		
1-	असीगंगा-1 (4.5 मे०वा०)	182.13
	योग	182.13
(ख) नाबार्ड की RIDF-XIV के अन्तर्गत		
1-	उर्गम (3 मे०वा०)	41.85
2-	चिरकिला (1.5 मे०वा०)	28.00
3-	मगौरी (0.80 मे०वा०)	47.90
4-	कन्धोटी (2 मे०वा०)	09.52
5-	कुलागाड़ (1.2 मे०वा०)	21.50
	योग	148.67
	महायोग	330.70

- स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।
- स्वीकृत धनराशि के आगणनों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाय अथवा नियमानुसार पूर्व से अनुमोदित एवं चालू कार्यो पर ही व्यय किया जाय।
- धनराशि का उपयोग नाबार्ड के गाईड लाईन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा नाबार्ड के पत्र सं० 1619/RIDF-XIII(Uttarakhand)/95PSC/2007-08, दिनांक 11.02.2008 एवं पत्र सं० 3351/RIDF-XIV(Uttarakhand)/99PSC/2007-08, दिनांक 30.08.2008 के प्रतिबन्धों/शर्तों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत ऋण पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर करना होगा।



४- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० ध्यय की गई धनराशि का रिम्बर्समेंट क्लेम दिनांक 31.01.2010 तक प्रस्तुत करेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

8- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। अद्युक्त की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् परियोजनाओं का वी.सी.आर. प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रस्ताव तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज क्लस्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाये।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है और निर्धारित समय में इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11- स्वीकृत ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदान सं० 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-01-जल विद्युत उत्पादन-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-04-नाबाई से जल विद्युत निगम को ऋण-30-निवेश/ऋण के नामें ढाल जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० 08/XXVII(1)/2010, दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मध्यस्थ

(सौरभ जैन)  
अध्यक्ष सचिव

संख्या- 77/1(2)/2010-04(1)/12/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- ~~मुख्य~~ सचिव-मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वज्जट, राजकोषीय नियोजन एवं ससाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

बाइबा से

(एम०एम० सेमवाल)

अनु सधिय